SECTION-F

INSTRUCTIONS REGARDING

ALLOTMENT OF LAND

SECTION-F
ALLOTMENT OF LAND

INDEX

Sr. No.	Subject	Letter No. and date	Page No.
1.	Regarding allotment of 3/2 biswas in Rural/Urban Area of State to houseless persons /families.	No.Rev.B.F(1)/2006-II dated 14/03/2016	1
2	Regarding allotment of 3/2 biswas in Rural/Unban Areas of State to houseless persons/families.	संख्या0रैव0बी0एफ0(1)1/2006–प्प दिनांक 28/05/2016	2
3	Regarding allotment of 3/2 biswas in Rural/Urban Areas of State to houseless persons/families	संख्या–रैव0बी0एफ0(1)1/2006–11 दिनांक 09/02/2015	3
4	Regarding allotment of 3/2 biswas in Rural/Urban Areas of State to houseless persons/families.	संख्या–डिव0कमर (शिमला) एल0आर0 –1–7(8)/2011–637–40 दिनांक 24 फरवरी, 2015	4
5	Regarding allotment of 3/2 biswas in Rural/Urban Areas of State to houseless persons/families.	संख्या0रैव0बी0एफ0(1)1/2006–प्प दिनांक 31/10/2015	5
6.	Regarding allotment of 3/2 biswas in Rural/Urban Areas of State to houseless persons/families.	संख्या0रैव0बी0एफ0(1)1/2006– प्प दिनांक 23/11/2015	6
7	Regarding allotment of 3/2 biswas in Rural/Urban Areas of State oto houseless persons/families	No.Rev.B.F(1)1-2/2006-I dated 22nd January,2014.	7-9
8	Regarding allotment of 3/2 biswas in Rural/Urban Areas of State to houseless persons/families.	No.Div.Commr.(SML)/LR-1-2(1)/2005-926-29 dated 24th February,2014	10
9	Regarding allotment of 2/1 biswas in Rural/Urban Areas of State to houseless persons/families.	No.Rev.B.F(1)1-2006(loose) dated 12/10/2010	11
10	Regarding allotment of 2/1 biswas in Rural/Urban Areas of State of houseless persons/families.	No.Rev.B.F(1)1/2006 dated Ist November,2010	12
11	Regarding allotment of 2/1 biswas land in Rural/Urban Areas of State to houseless persons/families.	No.Rev.B.F(1)1-2006 dated 28th February,2007	13-14
12	Regarding allotment of 2/1 biswas land in Rural/Urban Areas of State to houseless persons/families.	No.Rev.B-F(1)-1/2006 dated 5th October,2007	15
13	मकानहीन व्यक्तियों/परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 2 बिस्वा भूमि अलाट करने बारे।	संख्या–रैव0बी0एफ(1)–1/2006 दिनांक 8 मार्च,2006	16-18
14	मकानहीन व्यक्तियों/परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 1 बिस्वा भूमि अलाट करने बारे।	संख्या–रैव0बी0एफ(1)–1/2006 दिनांक 28 अप्रैल,2006	19-20
15	Allotment of land to the identified landless and other eligible persons-instructions regarding.	No.Rev.B-F(7)-1/94 dated 15th November,1995.	21-22

No. Rev. B.F(1)/2006-II
Government of Himachal Pradesh
Revenue Department

From

The A.C.S (Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh

To

All the Deputy Commissioners
In Hiamchal Pradesh

Dated Shimla-2 14.3 . 2016

Subject:- Regarding allotment of 3/2 biswa in Rural /Urban area of State to houseless persons families.

Sir,

In continuation of this department letter No. Rev. B.F(1)1/2006-1 dated 22nd January 2014 and subsequent letter of even no. dated 9.2.2015 on the subject cited above, I am directed to say that during the meeting of various welfare boards , it has been brought to the notice of Govt. that applications for allotment of 3/2 biswas of land in Rural/ Urban areas , to houseless person are not being proceed as expeditiously as should be, Resultantly , the applications are piling up day by day.

You are, therefore, requested to expedite the disposal of application for allotment of 3/2 biswas land in Rural/ Urban areas .

In addition to above , it has also come to the notice of the Govt. that in some cases such landless/ houseless persons have already occupied the Govt. land for construction of their residential houses/ sheds, especially by the persons belonging to Balmiki Community. In cases where such persons are eligible for allotment as per criteria laid down under the scheme, the land which is already under their occupation may be allotted to them upto the prescribed limit, subject to other norms applicable to the land .

The instructions be implemented in letter and spirit and the receipt of the communication may kindly be acknowledge

Yours faithfully,

Sd/-
Deputy Secretary (Revenue) to the
Government of Hiamchal Pradesh.

संख्याः रैव0बी0एफ0(1)1/2006–11
राजस्व विभाग,
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

उपायुक्त, बिलासपुर,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला–02 28/ 5/2016

विषयः– **Regarding allotment of 3/2 biswas in Rural/ Urban areas of Stat houseless persons/families.**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके कार्यालय के पत्र संख्याः बी.एल.एस–एल.आरसी–1(16)/2008–1–68252, दिनांक 18.2.2016 के सन्दर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त स्कीम के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को भूमि सम्बन्धित राजस्व गांव में ही आवंटित की जाये और यदि सम्बन्धित राजस्व गांव में भूमि उपलब्ध नहीं है तो निम्न वरीयता के आधार पर भूमि आंबटन किया जाये।

i. सम्बन्धित पटवार वृत में, यदि सम्बन्धित राजस्व गांव में भूमि उपलब्ध नहीं है।

ii. सम्बन्धित कानूनगो वृत में, यदि सम्बन्धित पटवार वृत में भूमि उपलब्ध नहीं है।

iii. सम्बन्धित उप–तहसील क्षेत्र में, यदि सम्बन्धित कानूनागो वृत में भूमि उपलब्ध नही है

iv. सम्बन्धित तहसील क्षेत्र, में यदि सम्बन्धित उप–तहसील क्षेत्र में भूमि उपलब्ध नही है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त क्षेत्रों में यदि अलग–अलग जगह भूमि उपलब्ध नही हैं तो पात्र आवेदकों को एक स्थान पर भी भूमि आंबटित की जा सकती है। जहां पर आंबटन के लिये गैर–वन भूमि उपलब्ध नही है वहां पर वन भूमि का आंबटन हेतु वन विभाग से अनुमति ली जाये।

<u>मामले में व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।</u>

भवदीय,
हस्ता/–
(राकेश मैहता)
उप–सचिव(राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः रैव0बी0एफ0(1)1/2006–IV
राजस्व विभाग,
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त(राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला–2 09.02.2015

विषयः– **Regarding allotment of 3/2 biswas in Rural/Urban areas of State of houseless person/families.**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के पत्र संख्याः रैव.बी.एफ. (1)1/2006–1 दिनांक 22 जनवरी, 2014 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकार के ध्यान में आया हैं कि उक्त स्कीम का कड़ाई से पालन नही किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना–पत्रों पर शीघ्र–अतिशोघ्र कार्रवाई की जाये। इसके लिए एक विशष अभियान छेड़ा जाये तथा जिले में यदि सरकारी भूमि उपलब्ध नही है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट इस विभाग को शीघ्र भेजें। इसके अतिरिक्त इस बारे त्रैमासिक प्रगति सूचना इस विभाग को हर तीन महीने में भेजें।

इसके अतिरिक्त उपायुक्तों से इस स्कीम के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण के लिए पत्र प्राप्त हो रहे हैं, अतः स्पष्ट किया जाता है कि यह स्कीम भूमिहीनों के लिए बनाई गई है, अतः जो भूमिहीन व्यक्ति लम्बे समय से हिमाचल में रह रहा है तथा जिसकी हिमाचल में रहने की स्थाई प्रकृति है उसे भूमि का आंबटन सम्बन्धित उपायुक्त स्व–विवेकानुसार करें। जो हिमाचल के व्यक्ति/परिवार हिमाचल के ही अन्य जिलों में रह रहे हैं उनको उनके स्थाई जिले में ही भूमि आबंटित की जायेगी। इस स्कीम के अन्तर्गत हि0प्र0 भू–मुजारियत अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत सरकार से अनुमति लेने की आवष्यकता नही है। जो भूमि आंबटित की जानी है यदि उस भूमि पर भू–संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होते है उसमें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्रवाई अपेक्षित है।

<u>मामले में व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।</u>

भवदीय,
हस्ता/–
(राकैश मैहता)
उप–सचिव(राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याःडिम–कमर(शिमला)एल0आर0–1–7(8)/2011–637–40
कार्यालय मण्डलायुक्त,
शिमला–2

दिनांक शिमला–2 24 फरवरी, 2015

सेवा में,

उपायुक्त,
शिमला, सोलन, सिरमौर एवं किन्नौर।

विशयः– **Regarding allotment of 3/2 biswas in Rural/ Urban areas of State of houseless persons/families.**

महोदय

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान उप सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः रैव. बी.एफ(1)1/2006–प्प दिनांक 09.02.2015 जो आपको भी सम्बोधित है (प्रति संलग्न) की ओर दिलाते हुए मुझे यह कहना है कि उक्त स्कीम का कड़ाई से पालन नही किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर शीध्र–अतिशोध्र कार्रवााई की जायें। इसके लिए एक विशष अभियान छेड़ा जाये तथा जिले में यदि सरकारी भूमि उपलब्ध नही है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व) विभाग हिमाचल प्रदेश को शीध्र भेजें। इसके अतिरिक्त इस बारे त्रैमासिक प्रगति सूचना हिमाचल प्रदेश सरकार को तथा इस कार्यालय को हर तीन महीने में भेजें।

इस स्कीम के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि यह स्कीम भूमिहीनों के लिए बनाई गई है। अतः जो भूमिहीन व्यक्ति लम्बे समय से हिमाचल में रह रहा है तथा जिसकी हिमाचल में रहने की स्थाई प्रकृति है उसे भूमि का आवंटन उपायुक्त स्व–विवेकानुसार करे। जो हिमाचल के व्यक्ति/परिवार हिमाचल के ही है अन्य जिलों में रह रहे है उनको उनके स्थाई जिले में ही भूमि आबंटित की जायेगी। इस स्कीम के अन्तर्गत हि0प्र0 भू–मुजारियत अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत सरकार से अनुमति लेने को आवष्यकता नही है। जो भूमि आंबटित की जानी है, यदि उस भूमि पर भू–सरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होते है उसमें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्रवाई अपेक्षित है।

कृपया इन निर्देशों को सभी सम्बन्धित राजस्व अधिकारियो में आगामी आवष्यक कार्यवाही करने हेतु परिचालित किया जाये तथा उक्त निर्देशो की पालना सुनिष्चित की जायें।

भवदीय,
हस्ता/–
(सोनिया ठाकुर)हि0प्र0से0,
सहायक मण्डलायुक्त,
कृते मण्डलायुक्त
शिमला मण्डल, शिमला–2

संख्याः रैव0बी0एफ0(1)1/2006–11

राजस्व विभाग,
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

उपायुक्त सोलन,
जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला–2 31/10ध्2015

विषयः– **Regarding allotment of 3/2 biswas in Rural/ Urban areas of State of houseless persons/families.**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके कार्यालय के पत्र संख्याः पेशो/एमसी (0–2 विस्वा) 2015–2594, दिनांक 01.09.2015 के सन्दर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों, में 2 विस्वा तथा ग्रमीण क्षेत्रों में 3 विस्वा भूमि आंबटन सम्बन्धी स्कीम समाज के भूमिहीन और कमजोर वर्गो के कल्याण के लिये बनाई गई है ताकि उन्हें मकान बनाने तथा जीवन की मूलभूत आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि उपलब्ध हो सके। अतः जरूरतमन्द लोगों को भूमि आंबटन करती वार आने वाली/छोटी–छोटी आपतियों/बाधाओं को अनुचित महत्व न दिया जाये बल्कि उनको अपने स्तर पर निपटाया जाये व वैधानिक रूप से आवष्यक अनापतियों के अतिरिक्त अन्य आपत्तियों को नजरअंदाज किया जाए।

मामले में व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,
हस्ता/–
(राकेश मैहता)
उप–सचिव(राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याःरैव.बी.एफ(1)1/2006–11
राजस्व विभाग,
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त(राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला–02 23.11.2015

विषयः– **Regarding allotment of 3/2 biswas in Rural/ Urban areas of State of houseless persons/families.**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान इस विभाग के पत्र संख्या रैव.बी.एफ(1)1/2006–1, दिनांक 22 जनवरी, 2014 के द्वारा जारी शहरी/ग्रमीण क्षेत्रों में 2/3 विस्वा भूमि आबंटन सम्बन्धी निर्देशों की ओर आकर्षित करते हुये यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त निर्देशों के अन्तर्गत भूमि का आबंटन पूर्व में बनी भू–आबंटन सम्बन्धी स्कीमोंः–1. H.P. Utilization of Surplus Areas Scheme, 1974, 2. H.P. Village Common Land Vesting and Utilization Scheme 1975, 3. Special Scheme for grant of Nautor Land to landless persons, 1975 and 4. H.P. Nautor Rules 1968 के अनुसार किया जाना है। उक्त स्कीमों के तहत जारी इस विभाग के पत्र संख्याः रैव.बी.एफ.(7)1/1994, दिनांक 15 नवम्बर, 1995 में शर्त लगाई गई है कि भूमि का आबंटन सड़क से 100 मीटर की दूरी पर ही किया जायेगा।

सरकार के ध्यान में आया है कि उक्त सड़क से 100 मी0 की दूरी वाली लगाई गई शर्त भूमिहीनों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए भूमि आबंटन में बाधा बन रही है क्योंकि वर्तमान में सरकार के पास आबंटन के लिये भूमि कम है। अतः उक्त के दृष्टिगत सरकार ने निर्णय लिया है कि जहां सड़क से 100 मी0 की दूरी पर आबंटन हेतु और भूमि उपलब्ध नहीं है वहां उक्त शर्त में छूट दे दी जाये।

मामले में व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,
हस्ता/–
(राकेश मैहता)
उप–सचिव(राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

No. Rev. B.F(1)1-2006-1
Government of Himachal Pradesh
Department of Revenue

From

The Principal Secretary-cum- F.C(Rev.) to the
Government of Himachal Pradesh.

To

1. The Divisional Commissioner
   Shimla/Mandi/Kangra at Dharamshala, H.P
2. All the Deputy Commissioners
   In Himachal Pradesh
3. The Settlement Officers
   Shimla, Kangra at Dharamshala, H.P.
4. All Sub-Divisional Officers(Civil)
   In Himachal Pradesh.
5. All Tehsildars & Naib-Tehsildars
   In Himachal Pradesh.

Dated Shimla- -2 22nd January, 2014

Subject:- Regarding allotment of 3/2 biswa in Rural/Urban areas of State to houseless person/families.

Sir,

In supersession of this Department letter No. Rev. B.F(1)1/2006 dated 28th February 2007, 05-10-2007 and 01-11-2010 on the subject cited above, I am directed to say that on reconsideration of the matter by the Government it has been decided to allot 3/2 biswa of land in rural/ urban areas in the form of following clarifications:-

i. The land is to be allotted out of the surplus land available in the districts under various schemes as such Himachal Pradesh Utilization of Surplus Areas Scheme, 1974, Himachal Pradesh, Village Common Land Vesting and Utilization Scheme, 1975 Special Scheme for grant of Nautor land to landless person, 1975 and H.P. Nautor Rules, 1968.

ii. The land available in the Government pool is to be allotted only by the Deputy Commissioners under the scheme .

iii. In Urban areas not much land is available with the government in any of the schemes mentioned above therefore, the land may have to be acquired for the purpose regarding which action may be taken depending on the number of eligible families in the urban areas.

iv. All such families whose income is Rs. 50,000/- per annum or less and who are houseless or those families whose entire land has been washed away in floods and have no suitable land for construction of residential house shall be eligible for allotment of 3 Biswas of land in rural areas and 2 Biswas of land in Urban areas even if such families are not included in the BPL list issued by the Rural Development Department.

v. The land allotted under these instructions shall be mutated in the name of both husband and wife and such land or house built on allotted land shall not be transferred by the allottee or his / her legal heir(s) , in any manners. In case the land so allotted or the house built thereon is transferred by the allottee or his/ her legal heir(s) the allotment so made shall stand cancelled and the land alongwith house if any, shall vest in the State Government free from all encumbrance.

vi. The provision/ requirement of Town and Country planning would govern such allotments.

In addition to above, it has further been decided that following persons will not be entitled for allotment of land under aforesaid instructions:-

1. Who have been allotted land under the various allotment schemes/ rules of the Government and have transferred/ sold the land.

2. Who have been conferred with the proprietary rights under H.P Tenancy and land Reforms Act 1972 and have been allotted the land under the scheme for allotment under Ceiling Act and have transferred/ sold the land.

3. Who have been allotted the land under any scheme of the government for landless and have transferred/ sold the land.

4. Whose father is alive. However the person who will inherit less than 3/2 biswa of land in Rural/ Urban area shall also be eligible for allotment so that his / her total holding is made upto 3/2 biswas.

With above instructions it is accepted that there remains no ambiguity in the scheme and all the deputy Commissioners will take initiative to fullfil the Government announcement in letter and spirit without any further loss of time. Monthly progress report may be sent by 7th of following month.

The Divisional Commissioner are requested to monitor the allotments of monthly basis and inform the Government.

The instructions may be implemented in letter and spirit and the receipt of the communication may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Sd/-
(Tarun Shridhar)
Pr. Secretary –cum- F.C(Rev.)
to the Govt. of H.P.

Immediate
Personal Attention
Time Bound

No. Div. Commr. (SML)LR-1-2(1)/2005-926-29
Office of the Divisional Commissioner
Shimla Division

Dated Shimla-2 24 February 2014

To

The Deputy Commissioner
Shimla, Solan Sirmaur and Kinnaur

Subject:- Regarding allotment of 3/2 biswa in Rural /Urban areas of State to houseless persons/ families.

Sir,

I am directed to invite your kind attention towards letter No. Rev. BF(1)1/2006 -1 , dated 22.1.2014 from the Principal Secretary-cum- F.C. (Rev.) to the Govt. of Hiamchal Pradesh on the subject cited above and to say that as per direction of the Govt. requisite information may please be supplied to this office on monthly basis by 5th of every month so that further action in the matter could be taken up accordingly.

"This may please be treated as MOST URGENT"

Yours faithfully,

Sd/-
(Sandeep Negi, HPAS)
Assistant Commissioner to the
Shimla Division, Shimla-2

FAX Message

No. Rev. B.F(1)1-2006(loose)
Government of Himachal Pradesh
Department of Revenue

From

A.C.S-cum- F.C (Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh

To

1. The Divisional Commissioner
   Shimla/Mandi/Kangra at Dharamshala, H.P.
2. All the Deputy Commissioners,
   In Himachal Pradesh.
3. The Settlement Officers.
   Shimla, Kangra at Dharamshala, H.P.
4. All Sub-Divisional Officers(Civil).
   In Himachal Pradesh.
5. All Tehsildars & Naib-Tehsildars.
   In Himachal Pradesh.

Dated Shimla- -2 12.10.2010

Subject:- Regarding allotment of 2/1 biswa land in Rural/Urban areas of State to houseless person/families.

Madam/Sir

In continuation of this Department letters of even number dated 28th February 2007 and 5th October, 2007 on the subject cited above I have been directed to State that the Government has decided to launch a special campaign to allot 1 biswa land to eligible Balmikies families in urban areas.

It has also been decided that in case no Govt. land is available for allotment for eligible families, the Deputy Commissioners may identify suitable land for acquisition in/ around urban areas.

In this regard pattas are proposed to be given to eligible families of balmiki Jayanti on 22nd October, 2010 at Solan.

The Deputy, Commissioner, Solan is requested to kindly get such cases pending before him examined/ proceed for allotment of Patts in favour of Balmikies families so that same could be handed over on the aforesaid occasion.

Yours faithfully,

Sd/-

Deputy Secretary (Revenue) to the
Government of Hiamchal Pradesh.

No. Rev. B.F(1)-1/2006
Government of Himachal Pradesh,
Department of Revenue

To

All the Deputy Commissioners
In Himachal Pradesh

Dated Shimla-2 the Ist November 2010

Subject:- Regarding allotment of 2/1 biswa land in Rural/Urban areas of State to houseless persons/families.

Sir,

In continuation of this department letters of even No. dated 28.February 2007 and 5th October ,2007 on the subject cited above, I am directed to say that on re-consideration , it has been decided that person who will inherit less than 2/1 biswa of land in rural/urban area be allotted land so that his/her total holding is made upto 2/1 biswa in rural/urban area as the case may be. All other conditions will remain the same.

2. Further , applications for allotment of land under the aforesaid instructions may be received upto 31.12.2010.

3. The monthly progress report(Rural ®/Urban (U) may be sent to this Department in the following performa:-

Previous balance		Application received during the month		Total Applications		Found eligible		Pending enquiry		Allotments made		Remarks /reason for non-allotment
R	U	R	U	R	U	R	U	R	U	R	U	

4. The monthly progress report may be sent by 10th of every month positively.

Yours faithfully,

Sd/
Deputy Secretary (Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Rev. B.F(1)1-2006
Government of Himachal Pradesh
Department of Revenue

From

The A.C.S-cum- F.C (Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh

To

1. The Divisional Commissioner
   Shimla/Mandi/Kangra at Dharamshala, H.P
2. All the Deputy Commissioners
   In Himachal Pradesh
3. The Settlement Officers
   Shimla, Kangra at Dharamshala, H.P.
4. All Sub-Divisional Officers(Civil)
   In Himachal Pradesh.
5. All Tehsildars & Naib-Tehsildars
   In Himachal Pradesh.

Dated Shimla-2 the 28th Feb. 2007

Subject:- Regarding allotment of 2/1 biswa land in Rural/ Urban areas of State to houseless persons/ families .

Sir,

In supersession of this Department letter of even number dated 8th March 2006 and 28th April 2006 and all earlier instructions issued on the subject cited above I am directed to say that on reconsideration of the matter by the Government it has been decided to allot 2/1 biswa of land in rural/urban area in the form of following clarifications:-

i) The land is to be allotted out of the surplus land available in the districts under various schemes such as Himachal Pradesh Utilization of Surplus Area scheme, 1974, Himachal Pradesh Village Common Land Wasting and Utilization Scheme 1975, Special Scheme for grant of Nautor Land to Landless person, 1975 and Himachal Pradesh Nautor Rules, 1968.

ii) The land available in the government pool is to be allotted only by the Deputy Commissioners under this Scheme.

iii) In Urban areas not much land is available with the Government in any of the Schemes mentioned above, therefore, the land may have to be acquired for the purpose regarding which action may be taken depending on the number of eligible families in the urban areas.

iv) All such families whose income is Rs. 10,000/- per annum or less and who are houseless shall be eligible for allotment of 2 Biswas of land in Rural Area and 1 Biswa land in urban area even if such families are not included in the BPL list issued by the Rural Development Department.

The land allotted under these instructions shall be mutated in the name of both husband and wife and such land or house built on allotted land shall not be transferred by the allottee or his her legal heir(s) in any manner. In case the land so allotted or the house built thereon is transferred by the allottee or his/her legal heir(s) the allotment so made will stand cancelled and the land alongwith house if any , shall vest in the State Government free from all encumbrances.

In addition to above , it has further been decided that following persons will not be entitled for allotment of land under aforesaid instructions.

1 Who have been allotted land under the Nautor Scheme of the Government and have transferred /sold the land.
2 Who have been allotted the land under the Land reforms & Tenancy Act and under the Surplus Ceiling Act and have transferred/ sold the land.
3 Who have been allotted the land under any scheme of the government for landless and have transferred /sold the land.
4 Whose father is alive.

With above instructions it is expected that there remains no ambiguity in the scheme and all the Deputy Commissioners will take initiative to fulfill the Government announcement in the letter and spirit without any further loss of time. Monthly progress report may be sent by seventh of following month.

The Divisional Commissioners are requested to monitor the allotments on monthly basis and inform the Government.

The instructions may be implemented in letter and spirit and the receipt of the communication may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Sd/-
Secretary (Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Rev. B.F(1)-1/2006
Government of Himachal Pradesh
Department of Revenue

From

A.C.S-cum- F.C (Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh

To

1. The Divisional Commissioner,
   Shimla/Mandi/Kangra at Dharamshala, H.P.
2. All the Deputy Commissioners,
   In Himachal Pradesh.
3. The Settlement Officers.
4. Shimla, Kangra at Dharamshala, H.P.
5. All Sub-Divisional Officers(Civil).
   In Himachal Pradesh.
6. All Tehsildars & Naib-Tehsildars.
   In Himachal Pradesh.

Dated Shimla- 2 5th October, 2007

Subject:- Regarding allotment of 2/1 Biswa Land in Rural /Urban areas of State to houseless/families

Sir,

In partial modification of this Department letter of even number dated 28th February 2007 on the subject cited above. I am directed to say that the Government has decided to increase the income limit from 10,000 per annum to Rs. 15,000 per annum fixed under condition / clarification No. (iv) in the aforesaid instruction .In addition to this the Government has decided that application so received be decided personally if the Government is in campaign mode:-

You are, therefore requested to consider the applications of all such applicants ,families , whose income is upto Rs. 15,000/- per annum or less for allotment of 2/1 Biswa of land in rural /urban areas.

The instructions may be implemented in letter and spirit and the receipt of the communication may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Sd/-
Deputy Secretary (Revenue) to the
Government of Hiamchal Pradesh.

संख्या रैव0बी0एफ0(1)–1/2006
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव(राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त उपायुक्त
   हिमाचल प्रदेश।
3. भू–व्यवस्था अधिकारी,
   शिमला, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हि0प्र0।
4. समस्त उप–मण्डलाधिकारी(नागरिक)
   हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त तहसीलदार/नायब–तहसीलदार,
   हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला–171002 8मार्च, 2006.

विषयः– मकानहीन व्यक्तियों/परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 2 बिस्वा भूमि अलाट करने बारे।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि प्रदेश सरकार भूमिहीन व्यक्तियों को गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करवाने हेतु कृत संकल्प है। प्रदेश सरकार एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा आवासहीन व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु विभिन्न योजनाएं जैसे, गांधी कुटीर योजना/इन्दिरा आवास योजना/राजीव गांधी आवास योजना इत्यादि चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत निर्धन, गृहहीन व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु वितीय सहायता प्रदान की जाती है जिनके लिए सरकार भूमि आवंटन हेतु कृत संकल्प है। इस सम्बन्ध में सरकार ने निर्णय लिया है कि पूर्व में उक्त स्कीमों के अन्तर्गत ऐसे गृहहीन परिवारों/व्यक्तियों को जोकि निम्नलिखित गृहहीन परिवार/व्यक्ति की परिभाषा में आते हो को ग्रामीण क्षेत्रों में 2 बिस्वा भूमि गृह निर्माण हेतु प्रदान की जाएः–

1. हिमाचल प्रदेश यूटिलाईजेशन आफ सरपल्स एरिया स्कीम, 1974.
2. हिमाचल प्रदेश विलेज का्मन, लैण्डज़ वैस्टिंग एण्ड युटिलाईजेशन स्कीम, 1975.
3. स्पेशल स्कीम फार ग्रांट आफ नौतोढ लैण्ड टू लैंडलैस परसन्ज़ 1975 और
4. हिमाचल प्रदेश नौतौड रूल्ज़ 1968.

इस उद्वेश्य हेतु 'गृहहीन परिवार/व्यक्ति' की परिभाषा इस प्रकार से होगीः–

''गृहहीन परिवार/व्यक्ति'' ऐसे व्यक्ति से है जिनके पास प्रदेश में घर नहीं है या गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है तथा जिसकी वार्षिक आय समस्त साधनों से राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिए निर्धारित आय से नीचे होय

परन्तु ऐसा व्यक्ति जिनके पिता जीवित हो को गृहहीन व्यक्ति नहीं माना जाएगा।''

इस सम्बन्ध में चयनित व्यक्तियों/परिवारों को भूमि आवंटन करने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं की अनुपालना करने होगीः–

(क) इस योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों द्वारा अपने आवेदन सम्बन्धित तहसीलदार/नाब–तहसीलदार को प्रस्तुत किये जाएगे। तहसीलदार/नायब–तहसीलदार पड़ताल करने के बाद प्रमाणित करेगें कि लाभार्थियों के ब्यान के मुताबिक पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार वास्तव में भूमिहीन है और उनके पास मकान निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि नहीं है, तथा उन्हें सरकारी भूमि दिया जाना अनिवार्य है।

(ख) सम्बन्धित तहसीलदार/नायब–तहसीलदार विभाग के राजस्व अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से पहले इस बात की पृष्टि करेगें कि उक्त लाभार्थी के पास कोई भूमि प्रदेश में उपलब्ध नहीं है जहां वह स्थाई तौर पर रह रहा है जहां वह मकान बनाना चाहता है। यदि उनके भूमिहीन हो जान की पुष्टि हो जाती है तथा यदि गाव में नियमानुसार सरकारी भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है तो पटवारी हल्का 0–2–00 बिस्वा अर्थात 75 वर्ग मीटर तक का ततीमा व राजस्व कागजात की नकले बना कर गरदवार कानूनगो के माध्यम से तहसीलदार फिर मौका पर जाकर छानबीन करने के उपरान्त अपनो रिपोर्ट तुरन्त सम्बन्धित उप–मण्डलाधिकारी(नागरिक) को भेजेगें। खण्ड विकास अधिकारी के नाम प्राप्त करने के एक माह के भीतर यह सारी प्रकिया पूर्ण हो जाएगी। इस बारे उप–मण्डलाधिकारी(नागरिक) द्वारा हर माह प्रगति रिपोर्ट उपायुक्त को भेजी जाएगी।

(ग) उपायुक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार की रिपोर्ट की जांच करने के उपरान्त पात्रता के आधार पर एक सप्ताह के भीतर 2 बिस्वा अर्थात 75 वर्ग मीटर सरकारी भूमि सम्बन्धित लाभार्थी के नाम स्वीकृत करेगें। वह अन्य मागदर्शन भूमिहीन आवासहीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जारी की गई हिदायतों से प्राप्त करें तदानुसार भू–अभिलेख में पृविष्टि की प्रकिया शीघ्र पूरी करना सूनिश्चित करेगें।

गांधी कुटीर योजना, इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना इत्यादि के अन्तर्गत निर्धन आवासहीन व्यक्तियों को वित्तीय अनुदान के साथ भूमि उपलब्ध करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी आवासहीन परिवार/व्यक्ति हैं जो इन योजनाओं में फिलहाल चयनित नहीं हो पा रहे हो लेकिन उन्हें भूमि आवंटित करना आवश्यक हो के लिए भी सरकार भूमि आवंटन हेतु कृत संकल्प है। प्रदेश सरकार एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न आवासीय योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा निर्णय किया गया है कि इन योजनाओं के अन्तर्गत चयनित भूमिहीन परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 2 बिस्वा भूमि उक्त स्कीमों/रूल्ज़ के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई जाए। इन आवासीयों योजनाओं के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को चयन प्रकिया पूर्ण होने पर खण्ड विकास अधिकारी ग्राम पंचायतों की राय से ऐसे लाभार्थियों के नाम व अन्य ब्यौरा सम्बन्धित तहसीलदार/नायब तहसीलदार को प्रेषित करेगें जिसके उपरान्त उन्हें उक्त प्रकिया अनुसार 2 बिस्वा भूमि आवंटित की जाएगी।

उक्त गृहहीन व्यक्तियों/परिवारों या आवसीय योजनाओं में चयनित व्यक्तियों को भूमि आबटन से पूर्व, जहां आवश्यक हो बन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की अनुमति भी ली जाए।

इन आदेशों के अन्तर्गत आबंटित भूमि का इन्तकाल पति–पत्नि दोनों के नाम तस्दीक किया जायेगा तथा ऐसी भूमि या उस पर बना मकान आवंटी द्वारा पुश्त दर पुश्त कभी भी किसी भी रूप में हस्तांतरित

नही की जायेगी/किया जाएगा। यदि आवंटी या उसके वारिसों द्वारा आवंटित भूमि या उस पर निर्मित मकान का हस्तांतरण किया गया तो उस भूमि का आवंटन रदद समझा जायेगा तथा ऐसी भूमि मय मकान, सभी विलंग्मों से भारमुक्त होकर सरकार से निहित हो जाएगी।

इन आदेशों के लागू होने के फलस्वरूप पूर्व आदेश सं0 रैव0बी0एफ0(7)–4/95 दिनांक 30–9–1995 तथा पत्र संख्या 9–13/71–रैव0बी–V, दिनांक 4–12–2002 निरस्त किए जाते हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि अपने जिला से सम्बन्धित समस्त उपमण्डलाधिकारियों एवं तहसीलदरों/नायब तहसीलदारों को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु निर्देश जारी करके पात्र व्यक्तियों/परिवारों को तुरन्त भू–आवंटन सुनिश्चित करें तथा इस सम्बन्ध में मासिक प्रगति सूचना इस विभाग को उपलब्ध करवाएं।

भवदीय,

हस्ता/–

उप–सचिव(राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकारी।

संख्या रैव0बी0एफ0(1)–1/2006
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव(राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त उपायुक्त
   हिमाचल प्रदेश।
3. भू–व्यवस्था अधिकारी,
   शिमला, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हि0प्र0।
4. समस्त उप–मण्डलाधिकारी(नागरिक)
   हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त तहसीलदार/नायब–तहसीलदार,
   हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला–171002 28अप्रैल, 2006.

विषयः– मकानहीन व्यक्तियों/परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 1 बिस्वा भूमि अलाट करने बारे।

महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 8 मार्च 2006 के कम को जारी रखते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकार प्रदेश मं भूमिहीन व्यक्तियों को गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करवाने हेतु कृत संकल्प है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में भी निर्धन, गृहहीन व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु एक–एक बिस्वा भूमि प्रति परिवार की दर से भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी उक्त पत्र में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में ऐसे गृहहीन परिवारों/व्यक्तियों को जो उक्त पत्र में पात्रता हेतु दी गई परिभाषा में आता है को एक–एक बिस्वा भूमि प्रति परिवार की दर से भूमि आवंटित की जाए।

जहां तक भूमि आंबटन हेतु दी गई प्रकिया का प्रश्न है, उक्त पत्र मे दी गई प्रकिया के अतिरिक्त, शहरी निकायों जैसे म्यूनिसिपल कोरपोरेशन, म्यूलिसिपल कामेटीज, नगर पंचायत इत्यादि जिसमें आवंटित की जाने वाली भूमि पडती/आती है, के परामर्श से गृहहीन परिवार/व्यक्ति को भूमि उपायुक्त द्वारा आवंटित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन शहरी क्षेत्रों में आबंटन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, में भूमि अधिग्रहण करके आबंटित की जाए।

इन दिशा निर्देशों के अन्तर्गत आबंटित की गई भूमि पर इस विभाग के उक्त पत्र में दर्शाई गई सभी शर्तें लागू होगी।

अतः आपसे निवेदन है कि अपने जिला से सम्बन्धित समस्त उपमण्डलाधिकारियों एवं तहसीलदरों/नायब तहसीलदारों को इस कार्यकम के कार्यान्वयन हेतु निर्देश जारी करके पात्र

व्यक्तियों/परिवारों को तुरन्त भू–आवंटन सुनिश्चित करें तथा इस सम्बन्ध में की गई प्रगति की मासिक प्रगति सूचना इस विभाग को उपलब्ध करवाएं।

भवदीय,

हस्ता/–

उप–सचिव(राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

No. Rev. B-F(7)-1/94
Government of Himachal Pradesh
Department of Revenue

From

The F.C. –cum-Secretary (Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh,

To

All the Deputy Commissioners
In Hiamchal Pradesh

Dated Shimla-171002 the 15th November, 1995

Subject:- Allotment of land to the identified landless and other eligible persons-instructions regarding.

Sir,

I am directed to say that the State Government have formulated the following three schemes in order to grant land to the landless and other eligible persons in the Pradesh namely:-

(i) Special grant for Nautor Land to Landless and other eligible persons.
(ii) Utilization of Surplus Area Scheme, 1975
(iii) H.P. Village Common Lands Vesting and Utilization Scheme, 1975.

2. With a view to identify the landless and other eligible persons in the Pradesh, two surveys were got conducted in 1981 and 1983 and most of the persons so identified have been granted land under the above referred three schemes but a few persons were left to whom the land could not be allotted for the reason that either the suitable land was not available near the places where they reside or such identified remaining persons were not willing to move to such far off places where such suitable land is available. These left out persons mostly belong to districts of Kullu . Chamba, and Kangra. In the Districts of Kullu and chamba , the Government land is classified as ‘Forest land’ and as such land can not be allotted unless the ‘forest land’ is de-notified under the Forest Conservation Act 1980 in consultation with the Government of India by the Forest Department . The Govt .has since stopped allotment of land except by specific relaxation.

3. Since the Government have been monitoring the progress of allotment of land to landless and other eligible persons under the above schemes, it has been brought to the notice of the Government that these allotted land previously face problems of attestation of mutation, delivering possession and exchange of cultivable land in lieu of un- cultivable land etc. to the allottees . With a view to remove these and after due consideration, the Govt. have now decided that such cases should be dealt with by respective districts Collector sympathetically and after proper verification/ inspection on the spot they should initiate action to review the cases of following nature as per rules and instructions:-

(i) The persons who were allotted land and where the pattas/ certificate and mutations have not been attested, the same should be issued/ attested immediately:-

(ii) The persons who have been allotted land but the same is not suitable for cultivation/ horticulture be given another area by cancelling the previous allotment, if available;

(iii) In case where the allottee is in possession of land at place other than the place where it was allotted , the same may be sanctioned to them upto the extent of allotment made to them by cancelling, previous allotment , if the land so occupied is deemed justified for allotment.

The District Collectors may take suitable action to resolve the long standing problems of the allottees who have been allotted land under the above schemes only as per above direction. In case on 3(ii) and 3(iii) above while reviewing the cases of land given in exchange or in possession it should be ensured that land now being given is 100 meter away from road, is not a prime land, land situated in a market or community place and is not prohibited by any other act / regulation or orders of any civil court. They are further requested to intimate the number of such cases in their respective districts and also the progress made in this behalf to the Government.

4. Kindly acknowledge receipt.

Yours Faithfully

Sd/-
F.C.-cum Secretary (Rev.) to the
Government of Himachal Pradesh.